Impact of Hanumantha Rao Committee recommendations

3376. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government are considering the impact of the Hanumantha Rao Committee's recommendations vis-a-vis freight charge and abolition of ECA allocation in West Bengal, where urea production is nil though the consumption during kharif season itself is now around five lakh tonnes; and

(b) whether in view of the above, top priority is being given to re-start the only urea producing unit at Durgapur immediately; if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) The requirement of urea for West Bengal, as per the allocations made under the Essential Commodities Act (ECA), 1955, is being met in full through multi-source supplies. No decision has been taken on the recommendation of the Fertilisers Pricing Policy Review Committee headed by Prof. C.H. Hanumantha Rao regarding discontinuance of the ECA allocations.

Due to resource constraints, it has not been possible to provide additional budgetary support to Hindustan Fertilizers Limited for undertaking the capital investment on replacement/ renovation of critical equipments required for resumption of production at Durgapur plant.

Revival Plan for IDPL

3377. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: SHRI RAHASBIHARI BARIK: DR. Y. LAKSHMI PRASAD:

Will the Miniser of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd. (IDPL) has submitted a Rs. 834 crore revival plan to his Ministry;

(b) whether all the ailing public sector drug companies could be revived with that amount; and

(c) if so, the steps taken by his Ministry to clear the proposal, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) According to Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (IDPL), the total cost of its Revival plan submitted by them on 1.6.1998 with a cut-off date of 30.9.1998, is Rs. 834 crores.

(b) No, Sir.

(c) Not applicable.

यूरिया तथा अन्य उर्वरकों का आयात

3378. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्लाः** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत माह और वर्षों में बहुत बड़ी मात्रा में यूरिया तथा अन्य उर्वरकों का सरकार द्वारा आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरिया के आयात के संबंध में लिये गए निर्णय में आयातित यूरिया की किस्म और मात्रा को ध्यान में रखा गया था;

(ग) क्या आयातित यूरिया की किस्म अत्यधिक घटिया और निम्न स्तर की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि घटिया किस्म का यूरिया आयात न किया जाए;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई उच्च-स्तरीय जांच करवायी गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिसका आयात सरकारी खाते में किया जाता है। नियंत्रणमुक्त अन्य प्रमुख उर्वरकों अर्थात् डी ए पी और एम ओ पी का आयात निजी व्यवसाय खाते मे किया जाता है।

आयात, मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिये किये जाते हैं। यूरिया के लिए आवश्यकता अनुमान सुस्थापित अन्तर-मंत्रालीय पद्धति के माध्यम से आंकी जाती है। अन्य उर्वरकों के लिए इसका निर्धारण, कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत स्कीम के ढांचे के अंतर्गत चल रही मांग तथा आपूर्ति की बाजार शक्तियों के द्वारा किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान तीन प्रमुख उर्वरकों के आयात नीचे दिये गये हैं:—

(लाख मी० टन में)

वर्ष	यूरिया	डी ए पी	एम ओ पी
1995-96	37.82	15.14	21.92
1996-97	23.28	5.34	10.21
1997-98	23.89	14.60	19.00

(ख) से (च) यूरिया के आयात नामित सरणीकरण एजेंसियों के माध्यम से किये जाते हैं। आयातित यूरिया की गुणवत्ता विशिष्टियां निर्धारित की गई हैं और इनका अत्यधिक सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जाता है। आयातित यूरिया की गुणवत्ता जांच के लिए, इस प्रयोजनार्थ स्थापित की गई केन्द्र तथा राज्य प्रयोगशालाओं के माध्यम से अवतारण बन्दरगाहों पर ही व्यवस्था है। जिन मामलों में निर्धारित गुणवत्ता विशिष्टियों से विचलन ध्यान में आते हैं, उनमें सरणीकरण एजेंसियों के माध्यम से शास्ति लगाई जाती है। "सी विनस" के मामले में जिसमें 11,736 मी० टन आयातित यूरिया स्तर का नहीं पाया गया था, उसकी नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० के कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) से जांच कराई गई थी तथा शास्ति के अलावा सरणीकरण एजेंसियों से निम्न स्तर के यूरिया की लागत भी वसूल की गई थी।

Gas Cracker unit at Tengakhat

3379. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) how far the MOU regarding construction of gas cracker unit at Tengakhat of Assam is being implemented;

(b) the details of the progress of implementation; and

(c) by when it will be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (c) The Assam Industrial Development Corporation (AIDC), a State Government Undertaking, proposed for setting up of gas cracker. Letter of Intent (LOI) LI:59 (91) dated 25.1.91 was issued for setting up of a gas cracker of 3 lakh TPA Ethylene, which was subsequently transferred to Reliance Assam Petrochemicals Ltd. (RAPL), a joint venture between AIDC and Reliance Industries Ltd. (RIL).

Government of Assam have identified 1262 acres of land at Tengakhat of which 128 acres of land have already been handed over to RAPL. Ministry of Petroleum and Natural Gas has committed for supply of gas for producing 2 lakh TPA of Ethylene at a concessional price for a period of 15 years. Gas supply agreement between RAPL and Oil India Ltd. (OIL) is in advance statge of discussions. RAPL has identified 3.2 lakh TPA Naphtha to be used as supplementary feedstock. Department of Chemicals & Petrochemicals has recommended to Ministry of Petroleum and Natural Gas for allocation of aforesaid Naphtha. For smooth operation of gas cracker, a